RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 10 JULY TO 16 JULY 2024 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 42 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

जीएसटी के सात साल में कर वसूली बढ़ी, करों का अनुपालन सरल लेकिन चुनौती अभी भी Page 3

FDI के लिमिट की समीक्षा करेगी सरकार Page 5

सैमसंग इंडिया ने 'सॉल्व फॉर टुमॉरो' की 100 टीमों की पहली सूची जारी की Page 7

editorial

एआइ पर बड़ी पहल

दुनियाभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति हुई है. इसके साथ-साथ इसके दुरुपयोग और कुप्रभावों को लेकर चिंताएं भी बढ़ी हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि एआइ के मामले में भारत सरकार दो पहलुओं पर काम कर रही है- इसकी क्षमता को बढ़ाना तथा सुरक्षा के उपाय करना. बीते मार्च में कैबिनेट ने 'इंडिया एआइ मिशन' को स्वीकृति दी थी. अगले दो-तीन महीनों में इस मिशन को प्रारंभ कर दिया जायेगा. इसके लिए 10,300 करोड़ रुपये की योजना बनायी जा रही है. एआइ अनुसंधान को गति देने के लिए 10 हजार से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की खरीद होगी. साथ ही, अन्वेषण केंद्र, डाटा सेट आदि भी स्थापित होंगे. इस योजना में निजी क्षेत्र की भी भागीदारी होगी. इस मिशन से एआइ के विकास में निवेश बढ़ने की उम्मीद है. पहले से ही अनेक स्टार्टअप सक्रिय हैं तथा निजी कंपनियां डाटा केंद्र बना रही हैं. वैष्णव ने ग्लोबल इंडिया एआइ समिट को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि तकनीक तक सभी की पहुंच होनी चाहिए. इस संबंध में भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण उदाहरण है. बहुत कम समय में एआइ ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपयोगिता साबित की है. विशेषज्ञों की मानें, तो इसकी संभावनाएं असीमित हैं. ऐसे में भारत का यह मिशन बहुत आवश्यक पहल है. सरकार के आगे आने से प्रोग्रामरों, डाटा विशेषज्ञों तथा निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा. उल्लेखनीय है कि बीते कुछ वर्षों से केंद्र सरकार ने शोध एवं अनुसंधान के मद में आवंटन बढ़ाने का सिलसिला भी शुरू किया है. किसी अन्य तकनीक की तरह एआइ के दुरुपयोग के मामले भी सामने आने लगे हैं. भारत में डिजिटल मसलों से जुड़े कुछ कानून बने हैं और कुछ प्रस्तावित हैं. पर एआइ के क्षेत्र में विशिष्ट नियमन की आवश्यकता है. यूरोपीय संघ ने एक कानून बनाया है तथा अमेरिका में एक आधिकारिक आदेश जारी हुआ है. ऐसी पहलें नियमन का आधार बन सकती हैं. लेकिन जैसा कि वैष्णव ने रेखांकित किया है, प्रभावी तरीके से एआइ के बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन और विचार प्रक्रिया की आवश्यकता है. इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्कों का विस्तार वैश्विक है. कोई अपराधी कहां बैठकर हैकिंग कर रहा है या डाटा चुरा रहा है या धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा है, इसका पता लगाना तथा रोकथाम करना बहुत ही कठिन है. भू-राजनीतिक तनावों से ग्रस्त विश्व में तकनीक एक बड़ा हथियार भी बन चुकी है. ऐसे में वैश्विक स्तर पर नियमन और सहकार होना आवश्यक है. भारत डाटा सेंधमारी का बड़ा निशाना है. एआइ के जरिये भी देश का नुकसान करने की कोशिशें हो सकती हैं. ऐसे में विकास के साथ-साथ सतर्कता बरतना भी जरूरी है.

बाजार में हाहाकार

900 अंक फिसला सेंसेक्स

एजेंसी। भारतीय शेयर बाजार में जहां बीते कारोबारी दिन मंगलवार को जोरदार तेजी देखने को मिली थी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 80,000 के स्तर के पार क्लोज हुआ था, तो वहीं बुधवार को ये तेजी जारी नहीं रह सकी और शेयर बाजार खुलने के कुछ ही मिनटों बाद धराशायी हो गया। हालांकि, BSE Sensex ने जैसे ही कारोबार शुरू किया अपना नया ऑल टाइम रिकॉर्ड लेवल छू लिया और अगले ही पल बिखरने लगा। सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा फिसलकर कारोबार कर रहा था, जबकि NSE Nifty 240 अंक से ज्यादा गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था।

रिकॉर्ड बनाकर धराशायी हुआ सेंसेक्स

सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ नजर आ रहा है। एर्हो इंडेक्स ने अपने पिछले बंद 80,351 से बढ़त लेते हुए 80,451.36 के नए ऑल टाइम हाई लेवल पर कारोबार तो शुरू किया, लेकिन ये तेजी कायम नहीं रख सका। खबर लिखे जाने तक सुबह 10.40 बजे पर सेंसेक्स 858.37 की गिरावट के साथ 79,505 के लेवल पर और 11 बजते- बजते ये 900 अंक की गिरावट के साथ 79,446 के स्तर पर पहुंचकर कारोबार कर रहा था।बीते कारोबारी दिन ये 80,000 के पार क्लोज हुआ था।

Nifty ने भी लगा दिया गोता

सेंसेक्स की तरह ही Nifty-50 भी बुरी तरह टूटा। एनएसई इंडेक्स ने अपने पिछले बंद 24,433 की तुलना में तेजी के साथ 24,459.85 के लेवल पर कारोबार शुरू किया था और कुछ ही मिनटों में ये सेंसेक्स के कदम से कदम मिलते हुए धड़ाम हो गया। खबर लिखे जाने तक NIFTY 252.95 या 1.04 फीसदी फिसलकर 24, 180.25 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था।

भारतीय पीएम का रुतबा

१० सालों में १६ देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, बना रिकॉर्ड

नई दिल्ली। एजेंसी

एक ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का रुतबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके सबूत हैं जिस तरीके से दुनिया के तमाम देशों में पीएम मोदी को लगातार उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नावाजा जाता है। इस कड़ी में रूस के दौरे पर गए पीएम मोदी को एक और सम्मान मिला है और वो है रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया। बता दें कि इस सम्मान की घोषणा 2019 में की गई थी।

पीएम मोदी का एक ग्लोबल लीडर के तौर पर ओहदा लगातार बढ़ता जा रहा है। विदेशी धरती पर उन्हें कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा है। बीते 10 सालों में लगभग 16 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। इसमें कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं।

किसी दूसरे देश से मिला नागरिक सम्मान का महत्व अपने आप में विशिष्ट होता है, आपको बता दें कि जब कोई देश किसी दूसरे देश के नेता को अपने यहां का सर्वोच्च पुरस्कार देता है, तो यह उन दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने में उस व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयास को दर्शाता है। इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा माना जाता है कि इस तरह के अवार्ड देने से दोनों देशों के संबंध और भी आगे बढ़ते हैं।

आईटीआर भरने के लिए चाहिए ये दस्तावेज, नहीं तो अटक जाएगा काम!

नई दिल्ली। एजेंसी

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन तेजी से करीब आ रही है। एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है। इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि अब तक दो करोड़ टैक्सपेयर्स अपना आईटीआर भर चुके हैं। पिछले साल 8.18 करोड़ आईटीआर भरे गए थे। यानी अभी छह करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने आईटीआर दाखिल नहीं किया है। इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से जल्दी से जल्दी आईटीआर भरने को कहा है ताकि आखिरी समय भीड़भाड़ से बचा जा सके। पिछली बार आखिरी दो दिनों में 18 लाख आईटीआर भरे गए थे। यहां हम आपको बता रहे हैं कि आईटीआर भरने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है।

फॉर्म-16

नौकरी करने वाले लोगों के लिए फॉर्म-16 सबसे अहम दस्तावेज होता है। इसकी मदद से आईटीआर फाइल किया जाता है। यह दस्तावेज किसी भी कर्मचारी को उसकी कंपनी की तरफ से दिया जाता है। इसमें कर्मचारी की सैलरी से टैक्स कटने की पूरी जानकारी होती है और साथ ही दी गई सैलरी की भी जानकारी होती है। आईटीआर में इससे जुड़ी जानकारी प्री-फिल्ड होती है। आपको इसे कन्फर्म करना होता है।

फॉर्म 26एएस

ये फॉर्म आयकर विभाग की तरफ से जारी किया जाता है। इसमें टैक्सपेयर्स की इनकम पर लगे टैक्स की पूरी जानकारी होती है। इसे आयकर विभाग की वेबसाइट से अपना पैन नंबर डालकर निकाला जा सकता है। आप चाहे तो अपने फॉर्म-16 और फॉर्म 26एएस की तुलना भी कर सकते हैं कि दोनों जगह टैक्स डिडक्शन समान है या नहीं।

इंटरेस्ट इनकम सर्टिफिकेट

अगर आपने किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोई एफडी कराई या फिर किसी और ब्याज मिलने वाली स्कीम में पैसे जमा किए हैं तो ब्याज से हुई इनकम का सर्टिफिकेट या फिर बैंक स्टेटमेंट भी रखना जरूरी है, ताकि आप उसकी सही जानकारी आयकर रिटर्न फाइल करते वक्त भर सकें। आप आयकर कानून की धारा 80 टीटीए के तहत 10 हजार रुपये तक की ब्याज से हुई कमाई पर टैक्स छूट पा सकते हैं।

टैक्स सेविंग का प्रूफ

बहुत से टैक्सपेयर्स टैक्स बचाने के लिए कुछ टैक्स सेविंग निवेश करते हैं। जो लोग ये दस्तावेज अपने एम्प्लॉयर को तय समय में नहीं दे पाते हैं, उन्हें आयकर रिटर्न फाइल करते समय इसका प्रूफ देने की जरूरत होती है। ये टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रूफ एलआईसी प्रीमियम की रसीद, पीपीएफ में निवेश की पासबुक, ईएलएसएस का सबूत, दान की रसीद और ट्यूशन फीस की रसीद आदि हो सकती है।

मेडिकल इंश्योरेंस का दस्तावेज

सेक्शन 80डी के तहत आप 25 हजार रुपये तक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए, आपके जीवनसाथी के लिए, बच्चों के लिए हो सकती हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप 50 हजार रुपये तक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। तो इन सबकी रसीद भी आयकर रिटर्न फाइल करते वक्त अपने साथ रखें।

अब जहाज भी बनाएंगे गौतम अडानी!

दुनिया को 30 साल में चाहिए 50,000 से अधिक कमर्शियल शिप

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत और एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस गौतम अडानी (Gautam Adani) अब जहाज निर्माण यानी शिपबिल्डिंग में उतरने की योजना बना रहे हैं। गुजरात के मुंद्रा में अडानी ग्रुप (Adani Group) के फ्लैगशिप पोर्ट पर जहाज बनाने का काम शुरू हो सकता है। इसकी वजह यह है कि चीन, जापान और दक्षिण कोरिया में अधिकांश यार्ड कम से कम 2028 तक पूरी तरह बुक हैं। यही वजह है कि दुनिया में जहाज ऑपरेट करने वाली बड़ी कंपनियों को शिपबिल्डिंग के लिए वैकल्पिक जगहों की तलाश है। इनमें भारत भी शामिल है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए अडानी ग्रुप शिपबिल्डिंग में उतरने पर गंभीरता से विचार कर रहा है।

अडानी ग्रुप देश का सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर है।मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 में भारत को शीर्ष 10 शिपबिल्डर बनाने और मैरीटाइम अमृत काल विजन में 2047 तक शीर्ष पांच में शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है। अडानी ग्रुप का प्लान देश की इस योजना में फिट बैठता है। दुनिया में कमर्शियल शिपबिल्डिंग मार्केट में भारत की हिस्सेदारी महज 0.05% है। दुनिया में कमर्शियल जहाज बनाने वाले देशों की लिस्ट में भारत 20वें स्थान पर है। देश की कुल विदेशी माल-ढुलाई आवश्यकताओं में भारतीय स्वामित्व वाले और भारतीय झंडे वाले जहाजों का हिस्सा लगभग 5% है। अडानी की जहाज निर्माण योजना को मुंद्रा बंदरगाह के लिए 45,000 करोड़ रुपये की विस्तार योजना में शामिल कर लिया गया है। इस योजना को हाल में पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिली है।

62 अरब डॉलर का मार्केट

अडानी ग्रुप ऐसे समय जहाज निर्माण में उतरने की तैयारी कर रहा है जब ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री डीकार्बनाइजेशन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए धीरे-धीरे ग्रीन शिप की ओर बढ़ रही है। एक अनुमान के अनुसार मौजूदा बेड़े को बदलने के लिए अगले 30 वर्षों में 50,000 से अधिक जहाजों का निर्माण किया जाना है। अडानी ग्रुप ने इस बारे में भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया। केपीएमजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2047 तक भारत का कमर्शियल शिपबिल्डिंग मार्केट 62 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। साथ ही इससे जुड़े सहायक उद्योग के 37 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इससे 1.2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलने की उम्मीद है।

केपीएमजी के अनुसार मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृत काल विजन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए भारतीय शिपयार्ड्स के सालाना उत्पादन को 2030 तक 0.072 मिलियन ग्रॉस टन से बढ़ाकर 0.33 मिलियन ग्रॉस टन और 2047 तक 11.31 मिलियन ग्रॉस टन तक बढ़ाने की आवश्यकता है। साल 2047 तक घरेलू कार्गो क्षमता में वृद्धि के अलावा भारतीय विदेशी कार्गो की न्यूनतम 5% ढुलाई प्राप्त करने के लिए, अतिरिक्त बेड़े की क्षमता की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू जहाज निर्माण की मांग अगले 23 वर्षों में 59.74 मिलियन ग्रॉस टन होने का अनुमान है। इनमें पुराने जहाजों का रिप्लेसमेंट भी शामिल है।

क्या है एडवांटेज

जानकारों का कहना है कि किसी नई कंपनी को इस सेक्टर में काफी समय लग सकता है लेकिन अडानी ग्रुप के लिए परिस्थितियां आसान हैं। उसके पास इसके लिए जमनी और और पर्यावरणीय मंजूरी है। हैवी इंजीनियरिंग में अडानी ग्रुप का यह पहला कदम होगा। एसईजेड का दर्जा मिलने से अडानी ग्रुप को अनेक वित्तीय और टैक्स चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। इन चुनौतियों के कारण स्थानीय कंपनियां चीन की शिपबिल्डिंग कंपनियों के साथ होड़ करने में असमर्थ है। भारत में आठ सरकारी यार्ड और करीब 20 निजी यार्ड हैं। लार्सन एंड टुब्रो चेन्नई के पास कट्टुपल्ली में एक यार्ड ऑपरेट करती है।

विमान ईंधन ATF 1.2% महंगा, कमर्शियल सिलेंडर 30 रुपये सस्ता, क्या पड़ेगा असर?

नई दिल्ली। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों के अनुरूप विमान ईंधन की कीमत में सोमवार को 1.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, होटल और रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल एलपीजी (19 किलोग्राम) सिलेंडर की कीमत में 30 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती की गई। सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन (एटीएफ) की कीमत 1,179.37 रुपये प्रति किलोलीटर या 1.2 फीसदी बढ़कर 96,148.38 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई। विमान ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर हवाई यात्रा की लागत पर पड़ेगा। इससे विमान किराये में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कमी से होटल और रेस्तरां के लिए खाना पकाने की लागत में कमी आएगी, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी।

जून में एटीएफ की कीमत में 6.5% की कटौती

इससे पहले एक जून को विमान ईंधन की कीमत में 6.5 फीसदी (6,673.87 रुपये प्रति किलोलीटर) की भारी कटौती की गई थी। मुंबई में एटीएफ की कीमत 88,834.27 रुपये प्रति किलोलीटर से बढ़कर 89,908.30 रुपये प्रति किलोलीटर कर दी गई। हर राज्य में स्थानीय करों के आधार पर कीमतें अलग-अलग होती हैं। इसके साथ ही तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 30 रुपये घटाकर 1,646 रुपये प्रति 19 किलोग्राम सिलेंडर कर दी है।

कीमतों में लगातार चौथी बार कमी

कीमतों में कटौती लगातार चौथी बार की गई है। इससे पहले एक जून को 69 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती की गई थी। एक मई को 19 रुपये प्रति सिलेंडर और एक अप्रैल को 30.5 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती की गई थी। हालांकि, घरेलू उपयोग में आने वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 803 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम पर यथावत है।

मिस्र को आसानी से होगा फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट

वहां की सरकार ने भारत में शुरू की यह सुविधा

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत से मिस्र (Egypt) को अब मीट और पॉल्ट्री समेत डेरी और अन्य फूड प्रोडक्ट्स (Food Products) का आसानी से निर्यात हो सकेगा। भारत से निर्यात किए जाने वाले मीट और पॉल्ट्री प्रोडक्ट (Meat & Paultry Products) मिस्र द्वारा निर्धारित हलाल स्टैंडर्ड (Halal Standard) के अनुरूप हो, इसके लिए एक बड़ा कदम उठा है। मिस्र ने यह सुनिश्चित करने के लिए बीते दिनों भारत में औपचारिक रूप से एक कार्यालय खोलने का फैसला किया। इसकी घोषणा भारत में मिस्र के राजदूत वील मोहम्मद अवाद हमेद ने की। इस अवसर पर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (APEDA) के अधिकारी भी उपस्थित थे।

भारत के लिए मौका

मिस्र के राजदूत ने बताया कि अब हलाल सर्टिफिकेशन के लिए भारत में एजेंसी की शुरुआत हो चुकी है। यह एजेंसी पूरे भारत में अपनी सेवाएं देगी। फिलहाल यह एजेंसी मीट और पॉल्ट्री प्रोडक्ट्स का सर्टिफिकेशन करेगी। बाद में इसमें डेरी और फार्मा भी जुड़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के मीट निर्यातकों के पास सुनहरा मौका है कि वे मिस्र को निर्यात किए जाने वाले मीट की मात्रा बढ़ा सकते हैं।

भारत है सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्टर

मिस्र में इस समय भारत सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्टर है। मिस्र के राजदूत ने बताया कि इस समय मिस्र में जितना मीट मंगाया जाता है, उसमें अभी भारतीय मीट की मात्रा 75 से 80 फीसदी के बीच है। हमें उम्मीद है कि आप मीट के कारोबार को 85 फीसदी, 90 फीसदी और 100 फीसदी तक बढ़ाना चाहेंगे। अगर आप इसे 100 फीसदी तक भी पहुंचाना चाहते हैं, तो मिस्र सरकार की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मिस्र की 99 फीसदी आबादी मांसाहारी है।

5,000 करोड़ रुपये का होता है निर्यात

भारत ने कैलेंडर ईयर 2023 में मिस्र को 630 मिलियन डॉलर करीब 5,000 करोड़ रुपये का मीट एक्सपोर्ट किया था। इससे पहले साल 2022 में यह करीब 600 मिलियन डॉलर का रहा था। इसमें हर साल बढ़ोतरी ही हो रही है। मिस्र भारत के अलावा ब्राजील, अमेरिका, यूरोप, जर्मनी आदि देशों से भी मीट मंगाता है।

हाल ही में शुरू हुआ है सर्टिफिकेशन

मिस्र की भारत में हलाल सर्टिफिकेशन एजेंसी हलाल मार्केट इंडिया के सीईओ डॉ. गासर अलसईद ने बताया कि साल 2020 से पहले वहां कोई हलाल सर्टिफिकेशन अनिवार्य नहीं था। उस समय विश्वास के आधार पर मीट खरीदा जाता था। लेकिन कुछ गड़बड़ी होने की वजह से इसे साल 2020 में लागू कर दिया गया। उन्होंने बताया कि भारत में हलाल सर्टिफिकेशन के लिए कोई फेसिलिटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। सिर्फ मिस्र सरकार द्वारा घोषित प्राइस लिस्ट लागू होगी। यदि कोई एक्सपोर्टर 40 फुट वाले किसी कंटेनर, जिसमें 28 टन तक मीट हो, का सर्टिफिकेशन कराना चाहता है तो उसे 2250 डॉलर का शुल्क चुकाना होगा।

जीएसटी के सात साल में कर वसूली बढ़ी, करों का अनुपालन सरल लेकिन चुनौती अभी भी

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए एक जुलाई का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। यह वही दिन है, जबकि सात साल पहले देश में वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी प्रणाली (GST System) लागू की गई थी। सरकार का कहना है कि इन सात वर्षों के दौरान वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली ने अनुपालन (Compliance) को सरल बनाया है। कर वसूली (Tax Collection) में उछाल आया है। इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई है। लेकिन टैक्स की चोरी को रोकने की कोशिश कर रहे नीति निर्माताओं के लिए नकली चालान और फर्जी पंजीकरण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

अप्रत्यक्ष कर में सरल प्रणाली

आप इस तथ्य को तो जानते ही होंगे कि एक जुलाई, 2017 को लागू वस्तु एवं सेवा कर (GST) ने कर व्यवस्था को सरल बनाया। इसने 17 करों और 13 उपकरों को 5-स्तरीय संरचना में व्यवस्थित किया। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर सीमा वस्तुओं के लिए 40 लाख रुपये और सेवाओं के लिए 20 लाख रुपये तक बढ़ गई। जब वैल्यू एडेड टैक्स या वैट का जमाना था, तब यह सीमा औसतन 5 लाख रुपये थी। जीएसटी ने राज्यों में 495 अलग-अलग सबमिशन (चालान, फॉर्म, घोषणाएं आदि) को घटाकर केवल 12 कर दिया है।

रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा

जीएसटी के सात वर्षों के दौरान पंजीकृत करदाताओं (Registered Taxpayers) की संख्या बढ़ कर 1.46 करोड़ हो गई है। साल 2027 में यह संख्या 65 लाख थी। यही नहीं, औसत मासिक जीएसटी राजस्व (GST Revenue) साल 2024-25 में लगभग 1.90 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह साल 2027-18 में 90,000 करोड़ रुपये था।

जीएसटी लागू होने से टैक्स के रेट घटे

जीएसटी प्रणाली लागू होने से कई वस्तुओं पर टैक्स के रेट में कमी हुई है। देखा जाए तो प्रभावी भारित औसत जीएसटी दर (Weighted average GST rate) साल 2017 से लगातार गिर ही रही है। देखा जाए तो कई आवश्यक वस्तुओं पर कर की दर अब प्री जीएसटी काल की तुलना में कम हो गई है। उदाहरण के लिए बालों में लगाये जाने वाले तेल और साबुन जैसी सामान्य वस्तुओं पर कर पहले कर दी कर 28 प्रतिशत थी। जीएसटी काल में इसे घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया। बिजली उपकरणों पर कर की दर पहले से 31.5 प्रतिशत थी, इसे घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया।

कई वस्तुओं से हटे टैक्स

जीएसटी ने कई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को टैक्स से छूट दी है। जैसे कि गैर-ब्रांडेड खाद्य पदार्थ, कुछ जीवन रक्षक दवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन, सैनिटरी नैपकिन, श्रवण सहायता के हिस्से, कृषि सेवाएं इत्यादि।

चुनौती अभी भी है

इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी चुनौती खत्म नहीं हुई है। भी भी टैक्स चोरी करने वाले धोखा देने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। कर अधिकारी नकली चालान बनाने और फर्जी जीएसटी पंजीकरण कराने वालों से जूझ रहे हैं। साल 2023 में ही देखिए तो जीएसटी इंटेलिजेंस निदेशालय (उउउछ) ने 1.98 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी का पता लगाया और 140 मास्टरमाइंडों को गिरफ्तार किया। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, बीमा और सेकेंडमेंट (जनशक्ति सेवाओं का आयात) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जीएसटी चोरी का पता चला।

कर वसूली बढ़ी है

यह भी सरकार की एक उपलब्धि ही है कि वित्त वर्ष 23-24 के लिए कुल जीएसटी संग्रह, 20.18 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस दौरान औसत मासिक संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा। यह एक परिपक्व जीएसटी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतीक है।

FD पर 8.5% ब्याज: SBI, ICICI, PNB, HDFC बैंक में से कौन ऑफर कर रहा है बेस्ट रेट?

नई दिल्ली। एजेंसी

एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, केनरा बैंक और यस बैंक जैसे कई बड़े बैंकों ने पिछले कुछ हफ्तों में अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) ब्याज दरों में बदलाव किया है। अगर आप एफडी में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो हमने आपका काम आसान कर दिया है। यहां हम आपको जुलाई में एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, केनरा बैंक, पीएनबी और यस बैंक की एफडी ब्याज दरों के बारे में बता रहे हैं। आप इनकी तुलना करके निवेश के लिए कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं।

SBI में FD पर कितना ब्याज?

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) आम नागरिकों को 3.50% से 7.10% और वरिष्ठ नागरिकों को 4% से 7.60% तक ब्याज की पेशकश कर रहा है। एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार, '12 अप्रैल 2023 से 400-दिन (अमृत कलश) की विशेष अवधि योजना के लिए ब्याज दर 7.10% है। वरिष्ठ नागरिक 7.60% की ब्याज दर के पात्र हैं। यह योजना 30 सितंबर 2024 तक मान्य रहेगी। संशोधित दरें 15 जून 2024 से प्रभावी हैं।'

आईसीआईसीआई बैंक एफडी रेट

आईसीआईसीआई बैंक आम नागरिकों को 3% से 7.20% और वरिष्ठ नागरिकों को 3.50% से 7.75% तक ब्याज दे रहा है। 7.75% और 7.20% की सबसे ज्यादा ब्याज दर 15 महीने से लेकर 18 महीने से कम की अवधि के लिए दी जाती है। ये दरें 5 जुलाई 2024 से लागू हैं।

एचडीएफसी बैंक का ब्याज कितना?

एचडीएफसी बैंक आम नागरिकों को 3% से 7.25% और वरिष्ठ नागरिकों को 3.50% से 7.75% तक ब्याज ऑफर कर रहा है। 7.25% और 7.75% की सबसे ज्यादा ब्याज दर 18 महीने से 21 महीने से कम की अवधि के लिए दी जाती है। ये दरें 5 जुलाई 2024 से लागू हैं।

केनरा बैंक का एफडी पर कितना रेट?

केनरा बैंक 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की एफडी पर आम जनता को 4% से 7.25% और वरिष्ठ नागरिकों को 4% से 7.75% तक ब्याज दे रहा है। 7.25% और 7.75% की सबसे ज्यादा ब्याज दर 444 दिनों की अवधि पर दी जाती है। संशोधित दरें 11 जून 2024 से लागू हैं।

पीएनबी की एफडी में कितना फायदा?

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) आम नागरिकों को एफडी पर 3.50% से 7.25% और वरिष्ठ नागरिकों को 4% से 7.75% तक रेट ऑफर कर रहा है। 7.25% और 7.75% की सबसे ज्यादा ब्याज दर 400 दिनों की अवधि के लिए है। ये दरें 10 जून 2024 से लागू हैं।

यस बैंक कितना दे रहा है इंटरेस्ट?

यस बैंक आम नागरिकों को 3.25% से 8% और वरिष्ठ नागरिकों को 3.75% से 8.50% तक ब्याज दे रहा है। 8% और 8.50% की सबसे ज्यादा ब्याज दर 18 महीने की अवधि के लिए है। ये दरें 8 जून 2024 से लागू हैं।

Moody's ने 6.8% पर बरकरार रखा भारत का GDP ग्रोथ अनुमान

नई दिल्ली। एजेंसी

ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2024 में भारत की जीडीपी के 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने के अपने अनुमान को बरकरार रखा है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि 2025 में भारतीय इकोनॉमी के 6.4 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी ने कहा, 'घरेलू और विदेशी मांग बढ़ने से इमर्जिंग मार्केट्स (EM) में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) की ग्रोथ को समर्थन मिल रहा है, जिसमें देश के हिसाब से व्यापक बदलाव हो रहा है।'

एजेंसी को उम्मीद है कि मौजूदा साल में महंगाई दर 2023 के 5.7 प्रतिशत से कम होकर 5.2 प्रतिशत पर आ जाएगी और अगले साल यह और गिरावट के साथ 4.8 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी। पिछले महीने सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, मई में महंगाई घटकर 12 महीने के निचले स्तर 4.75 प्रतिशत पर आ गई। उन्होंने कहा, 'इंडोनेशिया और भारत में मुख्य रूप से फूड प्रोडक्ट्स की कम कीमतों के कारण कोर इंफ्लेशन रेट धीमा हुआ है, लेकिन इन कीमतों की अस्थिरता दोनों देशों के लिए एक मुद्दा बनी हुई है।' मूडीज ने आगे कहा, 'इमर्जिंग मार्केट्स एशिया में रिटेल इंफ्लेशन की दर कम हो रही है और यह अधिकतर देशों में उनके केंद्रीय बैंक के लक्ष्य के करीब या नीचे है। साथ ही इन रिजन में मजदूरी बढ़ने का ट्रेंड भी कमजोर रहा है। हालांकि भारत और वियतनाम में मजदूरी सालाना आधार पर 5 प्रतिशत से अधिक बढ़ने के रुझान हैं।' भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में भारत के ग्रोथ अनुमान को पहले के अनुमानित 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है।

IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी सराहा

इससे पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज गति को सराहा है। IMF ने 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5 फीसदी की गति से बढ़ने का अनुमान लगाया है। इसी तरह, विश्व बैंक ने 2024 में भारत की विकास दर 7.5 फीसदी रहने का अनुमान जताया है।

बजट से उम्मीद: इस बार बजट में इंश्योरेंस पर घटना चाहिए टैक्स, डबल टैक्सेशन हो खत्म

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार अगर आम बजट में टैक्स में रियायत दे तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ आम लोगों को भी फायदा होगा। खासतौर से एन्युइटी पर डबल टैक्सेशन खत्म होना चाहिए। यह कहना है HDFC लाइफ इंश्योरेंस की सीईओ विभा पडलकर का।

सवाल - टर्म इंश्योरेंस को लेकर ऐसी राय है कि कंपनियां इसको पुश नहीं करतीं। आपका क्या कहना है?

इसको आंकड़ों में देखिए। दस साल पहले हमारे लिए और पूरे सेक्टर के लिए रिटेल लेवल पर टर्म प्लान की हिस्सेदारी 1% से भी कम थी। अभी यह 7-9% तक हो चुकी है। इसमें ग्रुप टर्म पॉलिसि भी जोड़ लें तो हिस्सेदारी 17-22% तक है। HDFC लाइफ की बात करें तो टर्म इंश्योरेंस के मामले में पिछले साल हमने अपनी ओवरऑल ग्रोथ की डबल रफ्तार हासिल की। टर्म इंश्योरेंस के मामले में 26% ग्रोथ रही। सम एश्योर्ड की ग्रोथ 52% थी। यह सब रिटेल का आंकड़ा है। ग्रुप टर्म इसके अलावा है। अभी हमारा प्रति व्यक्ति जीडीपी करीब 2500 डॉलर है। भारत दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा तो इसका असर दिखेगा। अवेयरनेस के साथ अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ेगी।

सवाल - IRDAI ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को मैच्योरिटी डेट से पहले सरेंडर करने पर सरेंडर वैल्यू से जुड़ा जो कदम उठाया है, उसके बारे में क्या राय है?

अभी सरेंडर वैल्यू के रेगुलेशन में यह हुआ है कि किसी वजह से कस्टमर को अगर पॉलिसी जारी नहीं रखनी हो तो हमें उन्हें ज्यादा पे करना होगा। रेगुलेटरी कंप्लेशन के हिसाब से जो मिनिमम सरेंडर वैल्यू देनी होती थी, उससे अधिक हम पहले भी दे रहे थे। इरडा ने सही कदम उठाया है। इंश्योरेंस सेक्टर को अपने बिजनेस मॉडल पर नए सिरे से नजर डालनी होगी।

सवाल - इरडा की 2022-23 की रिपोर्ट दिसंबर 2023 में आई थी। उसमें कहा गया कि मिससेलिंग की शिकायतें बढ़ी हैं। क्या मिससेलिंग के चलते फंस जाने से भी लोग पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं?

कभी-कभी हर इंडस्ट्री में मिससेलिंग हो सकती है। पॉलिसी बेचते समय ही कस्टमर को बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट की अगले 15, 20 या 25 साल की गारंटी है, जो और कोई फाइनैंशल प्रोडक्ट नहीं दे सकता है। लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर लिक्विडिटी चाहिए, तो उन्हें किसी और तरीके से फाइनैंशल प्लानिंग करनी चाहिए।

सवाल - इंश्योरेंस इंडस्ट्री आम बजट में क्या देखना चाहती है?

हमें देखना होगा कि हम किस तरह पेंशन सोसायटी बनेंगे। लोग जिस रिटायरमेंट कॉरपस से एन्युइटी खरीदते हैं, उस पर पहले ही टैक्स चुकाया जा चुका होता है। लेकिन जो एन्युइटी उनको मिलती है, वह भी पूरी तरह टैक्स्ड होती है। यह एन्युइटी का डबल टैक्सेशन है। अगर किसी ने 50 लाख रुपये की एन्युइटी खरीदी, तो इस 50 लाख पर टैक्स नहीं होना चाहिए। इसे कैपिटल गेंस टैक्स की तरह होना चाहिए और उस पर इंडेक्सेशन बेनेफिट मिलना चाहिए। इनकम पर टैक्स होना चाहिए, न कि कॉरपस पर। इसके अलावा टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाया जाना चाहिए। टैक्स रिलीफ से रिटायरमेंट के बाद के लिए बचत करने का प्रोत्साहन मिलेगा।

Budget 2024-25: बजट से पहले 'कबाड़' टायर पर क्यों हो रही बातें

नई दिल्ली। एजेंसी

वाहन टायर विनिर्माता संघ (एटीएमए) ने मंगलवार को कहा कि भारत में कबाड़ टायर के आयात पर अंकुश लगाने की जरूरत है। निकाय ने कहा कि देश कबाड़ टायर का 'डंपिंग ग्राउंड' बनता जा रहा है। एटीएमए ने वित्त मंत्रालय को अपनी बजट-पूर्व अनुशंसाओं में कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के बाद से भारत में बेकार/कबाड़ टायर का आयात पांच गुना से अधिक बढ़ गया है।

इसमें कहा गया, ''कबाड़ टायर का ऐसा अंधाधुंध आयात न केवल पर्यावरण व सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक है, बल्कि यह विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) विनियमन के उद्देश्य को भी कमजोर करता है। यह नियम जुलाई, 2022 से लागू है. एटीएमए के चेयरमैन अर्नब बनर्जी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, ''भारत में बेकार/कबाड़ टायर के आयात पर नीतिगत उपायों के जरिये अंकुश लगाने की आवश्यकता है ....''

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में अग्रणी टायर विनिर्माताओं में से एक के रूप में उभरा है, जहां घरेलू स्तर पर टायर का विनिर्माण सालाना 20 करोड़ से अधिक पर पहुंच गया है। इसलिए देश में पर्याप्त घरेलू एंड ऑफ लाइफ टायर (ईएलटी) क्षमता उपलब्ध है. एटीएमए ने अपनी बजटीय अनुशंसा में देश में घरेलू मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए प्राकृतिक रबड़ (एनआर) के शुल्क मुक्त आयात की भी मांग की है।

इसमें कहा गया, ''घरेलू स्तर पर निर्मित प्राकृतिक रबड़ की अनुपलब्धता के कारण टायर उद्योग की करीब 40 प्रतिशत प्राकृतिक रबड़ की आवश्यकता आयात से पूरी होती है। भारत में प्राकृतिक रबड़ के आयात पर शुल्क की उच्चतम दर उद्योग की प्रतिस्पर्धी क्षमता को प्रभावित करती है।'' एटीएमए ने टायर के प्रमुख कच्चे माल, प्राकृतिक रबड़ पर उलट शुल्क ढांचे के मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।

इसमें दावा किया गया, ''मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के तहत टायर पर मूल सीमा शुल्क 10-15 प्रतिशत है, जबकि देश में टायर का आयात और भी कम शुल्क (तरजीही शुल्क) पर किया जाता है। इसके प्रमुख कच्चे माल, यानी प्राकृतिक रबड़ पर मूल सीमा शुल्क बहुत अधिक (25 प्रतिशत या 30 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो) है।''

Budget 2024: आपका भी है बैंक में सेविंग अकाउंट? बजट में मिलने वाली है गुड न्यूज

नई दिल्ली। एजेंसी

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट अगले कुछ दिनों में पेश किया जाएगा। इसमें टैक्सपेयर्स को गुड न्यूज मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बचत खातों यानी सेविंग्स अकाउंट्स से अर्जित ब्याज पर टैक्स छूट की राशि को बढ़ाकर ?25,000 करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। पिछले हफ्ते फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रमुख अधिकारियों के साथ हुई बैठक में बैंकों ने इस संबंध में सुझाव दिया था। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि इसकी समीक्षा की जा रही है और बैंकों को कुछ राहत मिल सकती है, जिन्होंने जमा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की मांग की है। प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय बजट घोषणा के करीब आने पर लिया जाएगा।साल 2020 के बजट में एक अलग इनकम टैक्स रिजीम शुरू किया गया था। यह रिजीम सरल है लेकिन इसमें टैक्सपेयर्स के लिए सभी तरह की छूट बंद कर दी गई थी। पुरानी कर व्यवस्था के तहत, बचत खातों से सालाना 10,000 रुपये तक का ब्याज आयकर अधिनियम की धारा 80TTA के तहत कर मुक्त है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, यह सीमा 50,000 रुपये है और इसमें धारा 80 ऊऊँ के तहत फिक्स्ड डिपॉजिट से अर्जित ब्याज आय भी शामिल है। नए टैक्स रिजीम में ये लाभ नहीं मिलते हैं।

बैंकों की परेशानी

हालांकि, धारा 10(15) (ग) के तहत पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट्स पर ब्याज पाने वाले टैक्सपेयर्स व्यक्तिगत खातों के लिए 3,500 रुपये और संयुक्त खातों के लिए 7,000 रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं। बैंक दोनों टैक्स रिजीम के तहत यह फायदा देने की मांग कर रहे हैं। सूत्र ने कहा कि पुरानी सीमा को बढ़ाने और नई व्यवस्था में मौजूदा नियमों के तहत शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में बचत खातों से अर्जित टैक्स इनकम पर छूट देने के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। बैंकों ने इस बारे में एक प्रेजेंटेशन दी थी। बैंक बढ़ते क्रेडिट-डिपॉजिट रेश्यो को लेकर चिंतित हैं और बैंक डिपॉजिट्स को प्रोत्साहित करने की वकालत कर रहे हैं।

आरबीआई ने अपनी ताजा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा है कि परिवार वित्तीय बचत में विविधता ला रहे हैं। गैर-बैंकों और पूंजी बाजार में अधिक आवंटन कर रहे हैं। यह क्रेडिट-डिपॉजिट रेश्यो के बढ़ने का संकेत है। यह सितंबर 2021 से बढ़ रहा है। दिसंबर 2023 में यह 78.8% पर पहुंच गया था और मार्च के अंत में 76.8% पर था। इस हफ्ते की शुरुआत में, देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान उसके चालू खाता-बचत खाता जमा में पिछले तिमाही के मुकाबले 5% की गिरावट आई और यह 8.63 लाख करोड़ रुपये रह गया।

विदेशों में जमकर खर्च कर रहे हैं भारतीय, एक दशक में 29 गुना बढ़ोतरी

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय विदेशों में जमकर खर्च कर रहे हैं। पिछले एक दशक में इसमें 29 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसकी तुलना में फॉरेन रेमिटेंस में बहुत कम इजाफा हुआ है। रेमिटेंस का मतलब उन पैसों से है जो विदेश में काम करने वाले भारतीय कामगर स्वदेश भेजते हैं। वित्त वर्ष 2014 में भारतीयों ने विदेशों में 1.1 अरब डॉलर खर्च किए थे। वित्त वर्ष 2024 में यह राशि करीब 29 गुना बढ़कर 31.7 अरब डॉलर पहुंच गई। इस सबसे बड़ी वजह यह है कि बड़ी संख्या में भारतीय विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। इस अवधि में रेमिटेंस की 71% बढ़कर 70 अरब डॉलर से 120 अरब डॉलर हो गई है। हालांकि विदेशी रेमिटेंस हासिल करने के मामले में भारत अब भी नंबर 1 बना हुआ है। इस मामले में दूर-दूर तक कोई भारत के आसपास नहीं है। मेक्सिको (66 अरब डॉलर) सबसे ज्यादा विदेशी रेमिटेंस पाने के मामले में दूसरे नंबर पर है।बैंक ऑफ बड़ौदा के एक अध्ययन के अनुसार पिछले दशक में भारत में आने वाले रेमिटेंस में 5.5% की CAGR की दर से वृद्धि हुई है। इसका ग्लोबल ग्रोथ रेट 4% है। केवल मेक्सिको में यह भारत से ज्यादा 10% रही है। यही वजह है कि फॉरेन रेमिटेंस हासिल करने के मामले में मेक्सिको चीन को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। बीओबी की इकॉनॉमिस्ट अदिति गुप्ता ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2014 में केवल 1.1 अरब डॉलर से वित्त वर्ष 2024 में रेमिटेंस आउटफ्लो बढ़कर 31.7 अरब डॉलर हो गया। यह 40% से अधिक की सीएजीआर से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास के उभार से लोगों की इनकम बढ़ी है और विदेशी यात्राओं में ज्यादा खर्च से यह बात साबित होती है।

ग्लोबल ग्रोथ में सुधार

ग्लोबल ग्रोथ में धीरे-धीरे सुधार होने की उम्मीद है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोजोन में लेबर मार्केट मजबूत बने हुए हैं जबकि बेरोजगारी दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। यह रेमिटेंस के लिए अच्छा संकेत है। खाड़ी देशों से रेमिटेंस में कुछ मंदी दिख रही है। स्थिर तेल की कीमतों से इस क्षेत्र से रेमिटेंस को रिवाइव करने में मदद मिलेगी। वैश्विक स्तर पर रेमिटेंस के स्रोतों के संदर्भ में अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पर है। साल 2021 में दुनिया में कुल रेमिटेंस में इसकी हिस्सेदारी 25% से अधिक है। इसके बाद खाड़ी देश 17% के साथ दूसरे स्थान पर है। इनके अलावा जर्मनी, यूके और रूस भी ग्लोबल रेमिटेंस फ्लो में अहम कंट्रीब्यूटर्स हैं।

डिफेंस, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए आने वाली है गुड न्यूज, FDI के लिमिट की समीक्षा करेगी सरकार

नई दिल्ली। एजेंसी

डिफेंस और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए गुड न्यूज है। इन सेक्टर्स के लिए बजट में अहम घोषणा हो सकती है। सरकार डिफेंस, इंश्योरेंस और प्लांटेशन जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (इउ्ष्) सीमा की समीक्षा करने पर विचार कर रही है। साथ ही इस व्यवस्था को सरल बनाने के लिए प्रक्रियाओं पर विचार कर रही है। अधिकांश क्षेत्रों में उदार व्यवस्था है जहां ऑटोमैटिक अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) इस बात पर विचार कर रहा है कि डिफेंस के लिए निवेश मानदंडों को कैसे अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि सरकार रणनीतिक क्षेत्र में अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग को भारत में शिफ्ट करना चाहती है।मौजूदा नियम इस सेक्टर में 100% FDI की अनुमति देते हैं, जहां भी किसी यूनिट की एंट्री

से आधुनिक तकनीक तक पहुंच प्राप्त होती है। स्वचालित मार्ग के तहत 74% तक एफडीआई की अनुमति है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं। इनमें कुछ क्षेत्रों और छोटे हथियारों के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग शामिल है। इसके अंतर्गत कुछ शर्तें भी हैं, जिनकी समीक्षा की जा सकती है। बीमा क्षेत्र को 25 साल पहले विदेशी कंपनियों के लिए खोला गया था। सामान्य या जीवन बीमा कंपनी में एफडीआई की सीमा 74% है, जबकि बीमा मध्यस्थों में 100% एफडीआई की अनुमति है।

इंश्योरेंस सेक्टर

सामान्य बीमा कंपनियां कुछ वर्षों में लाभ में आ जाती हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस एक पूंजी-गहन बिजनस बना हुआ है। इसके लिए भारतीय और विदेशी भागीदारों को छह-सात वर्षों तक इक्विटी निवेश करने की आवश्यकता होती है। यह समीक्षा तब की गई है जब इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है और अधिकांश जीवन बीमा कंपनियां अब लाभ में हैं। लेकिन बीमा के साथ-साथ प्लांटेशन के लिए भी मंजूरी प्राप्त करना आसान नहीं होगा। विशेषकर तब जब बागानों के लिए इस व्यवस्था की समीक्षा का औचित्य स्पष्ट नहीं है। चाय, कॉफी, रबर और कई अन्य क्षेत्रों में 100% एफडीआई की अनुमति है।

विपक्ष में रहते हुए इंश्योरेंस पर बीजेपी के रुख को देखते हुए, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उसके सहयोगी दल इसमें किसी भी तरह के बदलाव के लिए आसानी से सहमत नहीं होंगे। अधिकारियों ने कहा कि समीक्षा का उद्देश्य एफडीआई का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करना और यह भी सुनिश्चित करना है कि अंतर-मंत्रालयी प्रक्रियाओं से संबंधित समय-सीमा का पालन किया जाए। यह समीक्षा ऐसे समय में की जा रही है जब भारत ज्यादा निवेश चाहती है। 'चीन प्लस वन' के नारे के जरिए निवेशकों को आकर्षित करने के बावजूद एफडीआई में स्थिरता देखी गई है। यदि कोई बदलाव होता है तो वह बजट घोषणाओं का हिस्सा हो सकता है।

अब दुबई मॉल में भी कर सकेंगे यूपीआई से भुगतान

नई दिल्ली। एजेंसी

संयुक्त अरब अमीरात और खाड़ी के अन्य देशों में ढेरों भारतीय रहते हैं। इसके साथ ही इन देशों में काफी भारतीय पर्यटक भी जाते हैं। अब इन पर्यटकों को वहां पेमेंट करने में काफी आसानी होगी। दरअसल, अब आसानी से मध्य पूर्व के देश संयुक्त अरब अमीरात में यूपीआई से भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिए नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया के इंटरनेशनल आर्म एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की बड़ी डिजिटल कॉमर्स कंपनी नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ साझेदारी की है।

कैसे होगा पेमेंट

एनपीसीआई इंटरनेशनल के सीईओ रितेश शुक्ला का कहना है कि अब यूएई में अब भारतीय यात्री या एनआरआई पॉइंट ऑफ सेल मशीन के माध्यम से क्यूआर कोड के जरिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) भुगतान कर पाएंगे। उनका कहना है कि यूएई के मर्चेंट्स के बीच यूपीआई पेमेंट की बढ़ती हुई स्वीकार्यता केवल भारतीय यात्रियों के लिए ही नहीं सुविधाजनक होगा, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनोवेटिव डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को भी प्रमोट करेगा।

लाखों भारतीय पहुंचते हैं वहां

खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) में भारतीय यात्रियों का आंकड़ा 98 लाख पहुंचने का अनुमान है। इस साल अकेले यूएई में 53 लाख के करीब भारतीयों के पहुंचने की संभावना है। भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) और एनपीसीआई इंटरनेशनल मिलकर यूपीआई को वैश्विक मंच पर बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। अब वहां यूपीआई पेमेंट सिस्टम काम करने से भारतीयों को और आसानी होगी।

भारत से बाहर कई देशों में चलता है यूपीआई

फिलहाल भारत के बाहर नेपाल, श्रीलंका, मॉरीशस, यूएई, सिंगापुर, फ्रांस और भूटान में यूपीआई से भुगतान किया जा सकता है। यूपीआई से डिजिटल भुगतान आसान होने के कारण इसके जरिए होने वाले लेनदेन की संख्या में साल दर साल इजाफा हो रहा है।

अरबों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं

एनपीसीआई के डेटा के मुताबिक, यूपीआई प्लेटफॉर्म पर जून में लेनदेन की संख्या 13.9 अरब थी। इसमें सालाना आधार पर 49 प्रतिशत का इजाफा देखा गया है। इस दौरान यूपीआई से औसत लेनदेन की संख्या प्रतिदिन 463 मिलियन रही और प्रतिदिन औसत 66,903 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ। यूपीआई के लेनदेन में बढ़त की वजह रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ना और यूपीआई को विदेशों में भी लॉन्च करना है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $651.99 अरब पर, पाकिस्तान का हाल कैसा?

नई दिल्ली। एजेंसी

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 28 जून को समाप्त सप्ताह में 1.71 अरब डॉलर घटा है। यह कम होकर 651.99 अरब डॉलर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पिछले सप्ताह कुल मुद्रा भंडार 2.92 अरब डॉलर घटकर 652.89 अरब डॉलर रहा था। इस साल सात जून को भंडार 655.82 अरब डॉलर के सर्वकालिक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। इसके उलट 28 जून को खत्म हुए हफ्ते के दौरान पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व 49.4 करोड़ डॉलर बढ़ गया। यह बढ़कर करीब 9.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

FCA में 1.25 अरब डॉलर की गिरावट

रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, 28 जून को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां (FCA) 1.25 अरब डॉलर घटकर 572.88 अरब डॉलर रहीं। डॉलर के संदर्भ में उल्लेखित विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं की घट-बढ़ का प्रभाव शामिल होता है।

गोल्ड रिजर्व में भी आई है कमी

रिजर्व बैंक ने कहा कि समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान स्वर्ण आरक्षित भंडार का मूल्य 42.7 करोड़ डॉलर घटकर 56.53 अरब डॉलर रह गया। विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 3.5 करोड़ डॉलर कम होकर 18.01 अरब डॉलर रहा। रिजर्व बैंक ने कहा कि आलोच्य सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के पास भारत की आरक्षित जमा 10 लाख डॉलर बढ़कर 4.57 अरब डॉलर रही। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कई कारण हो सकते हैं। इनमें व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप और विदेशी निवेश में कमी जैसे फैक्टर शामिल हैं।

एस्ट्राजेनेका करेगी भारत में करेगी 250 करोड़ का निवेश

नई दिल्ली। एजेंसी

दुनिया की टॉप दवा कंपनियों में शामिल एस्ट्राजेनेका (AstraZeneca) ने भारत में 250 करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की है। एस्ट्राजेनेका का इतिहास 100 साल से भी पुराना है लेकिन यह कोरोना काल में सुर्खियों में आई थी। कंपनी ने कोविशील्ड वैक्सीन विकसित की थी। भारत में कंपनी की सहयोगी एस्ट्राजेनेका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (AZPIL) चेन्नई में अपने ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के विस्तार पर 250 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी का दावा है कि इससे 1300 लोगों को रोजगार मिलेगा। कंपनी के भारत में बिजनस को इसी महीने 45 साल पूरे होने जा रहे हैं।

AZPIL के एमडी और कंट्री प्रेजिडेंट डॉ. संजीव पंचाल ने कहा कि चेन्नई फैसिलिटी का विस्तार इस बात का प्रमाण है कि कंपनी साइंस और इनोवेशन के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है। भारत प्रतिभाओं से भरा है और यहां का ईकोसिस्टम डिजिटल एडवांसमेंट्स के लिए भी काफी डायनैमिक है। यही कारण है कि भारत हमारे ग्लोबल ऑपरेशंस का हब है। अभी चेन्नई फैसलिटी 334,000 वर्ग फीट में फैली है और अगले छह महीने में इसमें करीब 180,000 वर्ग फीट स्पेस और जोड़ा जाएगा। इस तरह यह कंपनी का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बन जाएगा। अभी कंपनी के देशभर में 4,000 से अधिक कर्मचारी हैं।

कंपनी का इतिहास

साल 1999 में स्वीडन की एस्ट्रा एबी और ब्रिटेन की जेनेका पीएलसी के मर्जर से एस्ट्राजेनेका का गठन हुआ था। एस्ट्रा एबी की स्थापना 1913 में स्वीडन में डॉक्टरों के एक ग्रुप ने की थी। जेनेका की शुरुआत 1926 में इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज (घ्ण्) के रूप में हुई थी। कई साल तक यह ब्रिटेन की टॉप दवा कंपनियों में शामिल रही। 1999 में इन दोनों कंपनियों के मर्जर के बाद एस्ट्राजेनेका का जन्म हुआ। इसके बाद से इस कंपनी ने पिछले 25 साल में दुनियाभर में कई दवा कंपनियों का अधिग्रहण किया है। एस्ट्राजेनेका आज दुनिया की टॉप दवा कंपनियों में शामिल है। इसका मार्केट कैप 238.12 अरब डॉलर है और यह दुनिया की 46वीं बड़ी वैल्यूएबल कंपनी है। भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज 252.19 अरब डॉलर के साथ इस लिस्ट में 43वें नंबर पर है।

जुलाई में पंचक की शुरूआत कब से हो रही है, अभी से नोट कर लें सही डेट

पंचक कई तरह के होते हैं, इनकी शुरुआत सप्ताह के जिस दिन से होती है उसका अपना महत्व होता है. जुलाई में इस बार अग्नि पंचक लग रहे हैं. अग्नि पंचक को खतरनाक माना गया है.

इस दौरान अग्नि से संबंधी कार्य में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए. अग्नि पंचक का समय बहुत ही अशुभ माना जाता है. आइए जानते हैं जुलाई 2024 में अग्नि पंचक कब से शुरू हो रहे हैं, इस दौरान कौन से कार्य नहीं करना चाहिए. मंगलवार से शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहा जाता है. इस साल 23 जुलाई 2024 को अग्नि पंचक शुरू हो रहे हैं, इसका समापन 27 जुलाई 2024 को होगा.

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
इंदौर (म.प्र.)

अग्नि पंचक शुरू - 23 जुलाई 2024, सुबह 09 बजकर 20 मिनट

अग्नि पंचक समाप्त - 27 जुलाई 2024, दोपहर 01 बजे

अग्नि पंचक में क्या न करें

अग्नि पंचक के दौरान अग्नि देव प्रबल होते हैं, इसलिए इस अवधि के दौरान अग्नि से संबंधित कार्य जैसे यज्ञ, हवन, दीपक जलाना आदि वर्जित होते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अग्नि पंचक में विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू करना आदि शुभ कार्य नहीं करने चाहिए. अग्नि पंचक में निर्माण कार्य, औजार और मशीनरी कामों की शुरुआत करना अशुभ माना गया है. क्रोध पर नियंत्रण रखें नहीं तो नुकसान हो सकता है.

अग्नि पंचक का महत्व

अग्नि पंचक के 5 दिन बेहद अशुभ माने जाते हैं, इस दौरान शुभ कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इससे हानि होती है, परिणाम अशुभ मिलते हैं. पंचक के दौरान जिस समय घनिष्ठा नक्षत्र हो उस समय घास, लकड़ी आदि ईंधन एकत्रित नहीं करना चाहिए, इससे अग्नि का भय रहता है. दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा, यम की दिशा मानी गई है.

रात के समय बेडरूम से बाहर निकाल दें इन चीजों को, परिणाम जान उड़ जाएंगे होश

पं. राजेश वैष्णव
शनि उपासक ज्योतिष
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

घर में ज्यादातर समय हमारा बेडरूम में ही बीतता है. इन गलतियों की वजह से घर में कलह तो होती ही है साथ ही पैसों की तंगी भी आने लगती है. वास्तु अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको भूलकर भी बैडरूम में नहीं करना चाहिए, नहीं तो रातों की नींद, दिन का चैन छिन जाता है. व्यक्ति का जीवन संघर्षो से भर जाता है, हाथ में पैसा नहीं टिकता. आइए जानते हैं रात में सोने से पहले बेडरूम से कौन सी चीजों को बाहर निकाल देना चाहिए.

बैडरूम में क्या नहीं रखना चाहिए

जूते-चप्पल - वास्तु के अनुसार बैडरूम में कभी धूल से भरे जूते नहीं उतारने चाहिए. इससे घर की शातिं भंग होती है. नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है. व्यक्ति मानसिक तनाव से जूझने लगता है. घर में लक्ष्मी जी वास नहीं करती.

भूलकर भी न करें झाड़ू - झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है. बैडरूम में झाड़ू रखने से पति-पत्नी के बीच मनमुटाव होने लगते हैं. घर की बरकत चली जाती है. परिवार में प्रेम खत्म हो जाता है.

झूठे बर्तन - आमतौर पर लोग चाय, कॉफी पीने के बाद कप को बैडरूम में ही छोड़ देते हैं इससे नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है. ऐसे में आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है. व्यक्ति कंगाली की कगार पर आ जाता है. संघर्ष बढ़ने लगते हैं.

भूल से भी ऐसा न करें - बैडरूम में गंदे कपड़े, जूते और झाड़ू जैसी चीजों को कभी नहीं रखना चाहिए. ध्यान रखें की बेड के नीचे कचरा या कबाड़ न हो, इससे दुर्भाग्य पैर पसारने लगता है. चौखट पर आई लक्ष्मी जी लौट जाती है. तरक्की के रास्ते भी बाधित हो जाते हैं.

15 जुलाई को सूर्य देव चंद्र की राशि में गोचर करेंगे, इन 4 राशियों को होगा धन लाभ

डॉ. संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
9826384585

अखिल भारतीय ज्योतिष वास्तु संगठन के प्रदेश प्रवक्ता डॉ, संतोष वाधवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। ग्रहों का निश्चिच अवधि में एक से दूसरी राशि में प्रवेश करना गोचर कहा जाता है। इस 15 जुलाई को सूर्य देव चंद्र की स्वराशि कर्क में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य मिथुन से कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। ज्योतिष के अनुसार, सूर्य का यह गोचर इन तीन राशि के जातकों को लाभदायक रहेगा। आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये चार राशियां ।

सिंह राशि - सूर्य का गोचर सिंह राशि के जातकों का भाग्योदय होगा। कार्य-व्यापार से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। निवेश करने का सही समय है। आपके लिए यह समय नौकरी बदलने के लिए अनुकूल है। कर्क राशि - सूर्य के कर्क राशि में गोचर करने से कर्क राशि के जातकों तो 15 जुलाई के बाद समय बढ़िया शुरु होगा । आत्मविश्वास बढ़ेगा। कारोबार में मुनाफा और रिश्ते में मिठास आएगी।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों की हर बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। बड़े से बड़े काम आसानी से पूरे होंगे। व्यापार में लाभ होगा। इसके साथ ही कार्य में सफलता प्राप्त होगी। धन संबंधित लाभ हो सकते हैं। सेहत से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। बच्चों की एकाग्रता बेहतर होने से पढ़ाई-लिखाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे।

मीन राशि - सूर्य का राशि परिवर्तन मीन जातकों के लिए लाभदायक होगा। नौकरी पेशा लोगों का प्रमोशन हो सकता है। कामकाज में आ रही समस्या दूर हो सकती है और व्यापार में मुनाफा हो सकता है। आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल सकता है। मानसिक स्थिति में सुधार आएगा। वहीं, सेहत से जुड़ी समस्याएं दूर होगी। पुराने रोगों से मुक्ति मिलने वाली है।

इन 2 राशियों को होगा नुकसान - सूर्य के कर्क राशि में गोचर करने से इन दो राशियों को नुकसान मिलेगा। वृषभ और धनु राशि के जातकों को सावधानी से कदम उठाने होंगे। करियर, कारोबार और आर्थिक मोर्चे पर नुकसान हो सकता है।

सावन में इस बार 72 साल बाद बन रहा दुर्लभ संयोग, इन राशि वालों के मिट जाएंगे दुख-दर्द

हिंदू धर्म में सावन को पवित्र महीना माना जाता है, जोकि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है. इसलिए इस महीने भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना करने और व्रत रखने का विधान है. साथ ही सावन महीने में पड़ने वाले सोमवार का दिन भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया है.

पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन की शुरुआत 22 जुलाई 2024 से हो रही है, जिसका समापन 19 अगस्त 2024 को होगा. ऐसे में इस साल सावन का महीना 29 दिनों का होगा. वहीं ज्योतिष गणना के अनुसार इस वर्ष शिवभक्तों पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहेगी, क्योंकि कई शुभ और दुर्लभ योग में सावन की शुरुआत हो रही है.

कई दुर्लभ संयोग में सावन की शुरुआत

इस सावन में ऐसे संयोग बन रहे हैं, जोकि इसकी महत्ता को बढ़ा रहे हैं. बताया जा रहा है कि ऐसा दुर्लभ संयोग सावन में पूरे 72 साल बाद बना है. सावन की शुरुआत सोमवार के दिन से हो रही है और इसका समापन भी सोमवार को ही होगा. साथ ही सावन के पहले दिन सोमवार, प्रीति योग, आयुष्मान योग और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा. इन्हीं शुभ योग के कारण सावन का महीना बहुत शुभ होगा.

प्रीति योग : 21 जुलाई 2024 रात 11 बजकर 11 मिनट से अगले दिन 22 जुलाई 2024 की रात 8 बजकर 50 मिनट तक

सिद्धि योग : 22 जुलाई 2024 को पूरे दिन

आयुष्मान योग : 22 जुलाई 2024 रात 8 बजकर 50 मिनट से अगले दिन तक.

सावन के साथ इन राशियों के जीवन में होगा खुशियों का आगमन

सावन में बनने वाले इन शुभ और दुर्लभ योग का सकारात्मक प्रभाव कई राशियों पर पड़ेगा. इन राशियों पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहेगी और जीवन में चल रही परेशानियों से इन्हें छुटकारा मिलेगा. आइये जानते हैं सावन के साथ किन राशियों के जीवन में होगा खुशहाली का आगमन.

पंडित कपिल पाराशर
बनारस वाले ज्योतिष
आचार्य वास्तु विशेषज्ञ
6261493070

मेष : आपके लिए सावन का महीना बहुत शुभ साबित होगा और जीवन में खुशियों की वर्षा होगी. प्रेमी और वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा रहेगा और आर्थिक रूप से भी मजबूत रहेंगे.

सिंह राशि: सिंह राशि वालों के लिए सावन शुभता लिए आएगा. आपके करियर और कारोबार क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे और आय के नए-नए मार्ग प्रशस्त होंगे. भगवान शिव की कृपा से इस दौरान रुके हुए काम भी फिर से चल पड़ेंगे.

तुला राशि: तुला राशि वालों को सावन में धन, वाहन और जमीन का सुख मिलने की प्रबल संभावना है. साथ ही पैसों से जुड़ी परेशानी भी दूर होगी.

मकर राशि: आपके लिए सावन मास किसी वरदान से कम नहीं होगी. इस समय आप मनचाही सफलता को हासिल करेंगे और समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. धार्मिक कार्यों की ओर आपकी रुचि भी बढ़ेगी.

इस अंक में छिपी है लक्ष्मी जी की असीम पावर, दोनों हाथों से लुटाएं तो भी खत्म नहीं होती दौलत

पं. श्री रमेशचंद व्यास
(चैनपुरा वाले)
ज्योतिषयाचार्य एवं
रत्न विशेषज्ञ
मो. 9826345104

शास्त्रों में मां लक्ष्मी को धन-वैभव की देवी कहा गया है. मां लक्ष्मी का आशीर्वाद जिन लोगों पर रहता है, उनके पास धन-धान्य की कोई कमी नहीं रहती है. इसलिए हर व्यक्ति मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है. ज्योतिष की खास विद्या अंक ज्योतिष में अंकों पर जोर दिया जाता है. इसमें अंक या मूलंक के आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, जीवन, रुचि, सफलता और संघर्ष आदि के बाते में पता लगाया जाता है. मूलंक का अर्थ किसी व्यक्ति की जन्मतिथि के अंकों से होता है. मूलंक का अर्थ जन्मतिथि के अंकों के जोड़ को कहते हैं, जोकि 1-9 अंक के बीच की संख्या होती है.

किस अंक से है मां लक्ष्मी का संबंध

जैसा कि हमने बताया कि अंकज्योतिष के अनुसार हर अंक का किसी न किसी ग्रह या देवी-

देवताओं से संबंध होता है. इसी तरह मां लक्ष्मी के प्रिय अंक की बात करें तो, 6 अंक के साथ मां लक्ष्मी का खास संबंध होता है.

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 6, 15 या 24 तारीख को होता है, उनका मूलंक 6 होता है. ऐसे लोगों पर सदैव मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और इसलिए इनके जीवन में कभी भी पैसों का अभाव नहीं रहता है.

साथ ही 6 मूलंक वाले धन, ऐश्वर्य के धनी होते हैं और भौतिक सुख-सुविधाओं का आनंद लेते हैं. लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इन्हें कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है.

साथ ही मूलंक 6 वाले लोगों का स्वभाव भी बहुत बढ़िया होता है, जिससे दूसरे लोग तुरंत प्रभावित और आकर्षित हो जाते हैं. इनके सरल स्वभाव और विशेष गुणों के कारण ही इनकी सूची में मित्रों की संख्या भी अधिक रहती है.

5000 किलोमीटर दूर से आई खुफिया जानकारी

IGI एयरपोर्ट पर पकड़ी आटे जैसी गोलियां, कीमत 22 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। एजेंसी

तू डाल-डाल मैं पात-पात' दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर यह कहावत रोजाना ही सच होती है। एक तरफ दुनियाभर के तस्कर जो अवैध रूप से चीजों को लाने-ले जाने के लिए एक से एक दांव चलते हैं और दूसरी ओर कस्टम के अधिकारी उनकी हर चाल को विफल कर देते हैं। हालिया मामला दिल्ली से करीब 5 हजार किलोमीटर दूर से आए एक यात्री का है, जिसे आईजीआई पर तब गिरफ्तार कर लिया गया, जब उसके पास आटे जैसी करीब 70 गोलियां निकली। इसकी जांच करते ही अधिकारी चौंक पड़े, क्योंकि इन गोलियों की कीमत 22 करोड़ रुपये से भी ज्यादा रही।

दरअसल, इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा से कैमरून निवासी एक व्यक्ति अजूको नवाला आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरा। उसके साथ लगेज भी था और शान से इंटरनेशनल ट्रांजिट एरिया को पार कर रहा था। लेकिन, दिल्?ली से करीब 4,557 किलोमीटर दूर से आए इस व्यक्ति के साथ ही एक खुफिया जानकारी भी आईजीआई अधिकारियों को मिली और उन्होंने उस व्यक्ति को इमीग्रेशन गेट पर रोक लिया। पहले पूछताछ की और फिर तलाशी शुरू हो गई।

तलाशी में क्या निकला

कस्टम अधिकारियों ने उस व्यक्ति और उसके लगेज की तलाशी शुरू की तो छुपाकर रखी गई 1,472 ग्राम आटे जैसी गोलियां निकलीं। एक पैकेट में लिपटे 70 सफेद कैप्सूल को देखते ही कस्टम अधिकारी चौंक उठे। उन्होंने आनन-फानन में नारकोटिक्स विभाग के एक्सपर्ट को बुलाया और गोलियों की जांच की. जांच में पता चला कि आटे जैसी दिखने वाली यह सफेद गोलियां दरअसल कोकीन हैं और इसकी कीमत 22 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बताई जाती है।

अंतरराष्ट्रीय गिरोह का खुलासा

नारकोटिक्स विभाग की जांच में कन्फर्म होने के बाद नवाला को सेक्शन 43(B) और NDPS एक्ट के तहत कस्टडी में ले लिया गया। उससे पूछताछ के बाद मादक पदार्थ बेचने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का खुलासा हुआ। आईजीआई एयरपोर्ट के कस्टम विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर वरुण एन का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और जल्द ही बड़े गिरोह का खुलासा हो सकता है।

कैसे मिली खुफिया जानकारी

ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि इंटेलीजेंस ने पहले ही चेताया था कि कोकीन की बड़ी खेप भारत में आने वाली है। इसकी जानकारी मिलते ही कस्टम अधिकारी अलर्ट हो गए और एयरपोर्ट पर जांच अभियान शुरू कर दिया गया। हम इसमें सफल हुए और 22 करोड़ से ज्यादा कीमत की कोकीन बरामद हुई है। मामले की जांच अभी जारी है और इससे जुड़े नेक्सस का पर्दाफाश किया जाएगा।

नई गैलेक्सी वॉच एवं बायोऐक्टिव सेंसर

स्वास्थ्य के बारे में और भी ज्यादा सटीक जानकारी

इंदौर। एजेंसी

सैमसंग डिजिटल हेल्थ इनोवेशन के ज़रिए आपके स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती को ज़्यादा आसान और बेहतर बनाने के लिए गहन जानकारियों और कई स्वास्थ्य मानकों को एक साथ ला रहा है। इससे आपको ज्यादा असरदार और बेहतरीन स्वास्थ्य अनुभव मिलेगा। सैमसंग ने अपने बायोएक्टिव सेंसर की मदद से आपको ज़्यादा व्यापक, व्यक्तिगत और बेहद सटीक स्वास्थ्य डेटा देकर सरल और सटीक स्वास्थ्य निगरानी तक पहुंच प्रदान करने की पहल की है।

इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए, सैमसंग अपने बायोएक्टिव सेंसर के नवीनतम संस्करण के साथ स्वास्थ्य निगरानी में नए मानक स्थापित कर रहा है। यह सेंसर अगली गैलेक्सी वॉच में होगा और यह न केवल अधिक सटीक हेल्थ मेजरमेंट्स प्रदान करेगा, बल्कि वियरेबल डिवाइस पर पहले कभी नहीं देखी गई उन्नत प्रेडिक्टिव एवं प्रिवेंटिव वेलनेस सुविधाओं को भी सक्षम करेगा।

अगली गैलेक्सी वॉच आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए नए बायोएक्टिव सेंसर के साथ आएगी। इस सेंसर की डिजाइन में कई सुधार किये गये हैं जिसकी वजह से ये पहले की तुलना में अधिक सटीक स्वास्थ्य जानकारी प्रदान करता है। इससे आपको अपनी सेहत का बेहतर ध्यान रखने में मदद मिलती है। सैमसंग के इंजीनियरों ने इस नए सेंसर को बनाने में तीन मुख्य सुधार किए हैं: सबसे पहले लाइट रिसीविंग फोटोडायोड का प्रदर्शन बढ़ाया गया है, वहीं, लाइट-एमिटिंग डायोड (एलईडी) के अतिरिक्त रंग जोड़े गए हैं और उन्हें सेंसर में बेहतरीन ढंग से व्यवस्थित किया गया है।

सैमसंग ने प्रत्येक फोटोडायोड के प्रदर्शन को दोगुना से अधिक कर दिया है, कंपनी ने क्षमता को बरकरार रखने के लिए जरूरी फोटोडायोड की संख?या सफलतापूर्वक कम कर दी है। आठ की जगह अब केवल चार फोटोडायोड का इस्तेमाल किया गया है। इस बदलाव से सेंसर में काफी जगह बच गई है और इसका उपयोग बड़ी संख?या में तरह-तरह की एलईडी जोड़ने के लिए किया गया है। नए सेंसर में अब हरे, लाल और इन्फ्रारेड एलईडी के अलावा नीले, पीले, बैंगनी और पराबैंगनी एलईडी भी हैं। इन एलईडी, फोटोडायोड और खासतौर से डिजाइन किये गये फोटोडायोड को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करके, सैमसंग इनोवेशन को एक कदम आगे ले जा रहा है। इन सेंसर्स की मदद से अब वियरेबल्स पर स्वास्थ्य पर नजर रखने के अनछुए पहलुओं का अनुभव होगा।

सस्टेनेबल प्रोडक्शन और नवाचार पर प्राथमिकता के साथ भारतीय कपड़ा व्यापारी

गार्टेक्स टेक्सप्रोसेस इंडिया, न्यू दिल्ली 2024 में... लॉन्च करेंगे नए उत्पाद और प्रदर्शित करेंगे नवाचार

नई दिल्ली। एजेंसी

निर्माण क्षेत्र में आ रही गति, तेज़ी से सम्पादित होते फॉरिन ट्रेड एग्रीमेंट्स, कपड़ा निर्यात में वृद्धि के साथ ही सरकार के भारत को 'वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब' बनाने पर दिए जा रहे जोर ने भारतीय कपड़ा उद्योग के सभी हितग्राहियों के लिए आशाजनक अवसर खोल दिए हैं। इन सभी सकारात्मक पहलों से उत्पन्न होने वाला वस्त्र टेक्नोलॉजी और परिधान मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों का यह आशावाद आने वाले गार्टेक्स टैक्सप्रोसेस इंडिया में उनकी भागीदारी से साफ झलकता है, जो की नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि (आईआईसीसी) में 1 से 3 अगस्त तक होने जा रहा है। वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद, कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (सीआईटीआई) द्वारा मई 2024 में वस्त्र निर्यात और परिधान में क्रमशः 9.59% और 9.70% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो भारतीय वस्त्र उद्योग के उत्साह को बढ़ाने वाला एक सकारात्मक संकेत है। आईबीईएफ के अनुसार, भारतीय वस्त्र और परिधान का बाजार 10% सीएजीआर की दर से बढेगा और 2030 तक बढ़कर 350 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि निर्यात 100 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत के कपड़ा और परिधान निर्माताओं, कपड़ा मशीनरी कंपनियों, संबद्ध उद्योगों और भारत सरकार की भविष्य की योजनाओं और नीतियों से भारतीय कपड़ा क्षेत्र को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत के अग्रणी परिधान और वस्त्र निर्माण, डेनिम, एससेरीज, टेक्सटाइल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आदि के इस सबसे बड़े एक्सपो - गार्टेक्स टेक्सप्रोसेस इंडिया - में नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि के 15,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 600 से अधिक ब्रांड अपना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। भारत के अलावा इस प्रदर्शनी में चीन, इटली, जापान, सिंगापुर, ताइवान और यूएस जैसे देशों से भी टेक्सटाइल से जुड़े उद्योग कपड़ा बाज़ार में वैश्विक उत्कृष्टता का प्रदर्शन करेंगे। पूरी प्रदर्शनी के सभी स्टॉल बिक चुके हैं और भारत के कुछ अग्रणी ब्रांड जैसे की एटी इंक्स, ऑरा टेक्नोलॉजीज, बाबा टेक्सटाइल मशीनरी, बेंज एम्ब्रॉयडरी, ब्रिटोमैटिक्स इंडिया, चेतना फैशन, डीसीसी प्रिंट विजन, जेसिंथ डाइस्टफ इंडिया और टू कलर्स इसका हिस्सा बनेंगे। अंतरराष्ट्रीय ब्रांड में बाओयू, ब्रदर, डाटाटेक्स, ड्यूपॉन्ट, जैक, कंसाई, सिनसिम, सिरुबा, युमेई आदि शो को वैश्विक स्तर प्रदान करेंगे।

सैमसंग इंडिया ने 'सॉल्व फॉर टुमॉरो' की 100 टीमों की पहली सूची जारी की

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत के अग्रणी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सैमसंग ने अपनी एक बड़ी सीएसआर पहल - 'सॉल्व फॉर टुमॉरो' के लिए 100 टीमों को शॉर्टलिस्ट करने की घोषणा की है। यह पहल देशभर में नए-नए आविष्कार करने के सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस शॉर्टलिस्ट में 'स्कूल' और 'यूथ' ट्रैक से 50-50 टीमें शामिल हैं जो अब राष्ट्रीय शिक्षा और नवाचार प्रतियोगिता में आगे प्रतिस्पर्धा करेंगी।

इस वर्ष शॉर्ट लिस्टिंग क्षेत्रीय स्तर पर की गई है। इससे इस प्रतियोगिता को देश के सुदूर इलाकों जैसे कि ओडिशा कचर में खुर्दा और असम में कामरूप ग्रामीण और गुजरात में अमरेली में रहने वाले भारतीय इनोवेटर्स की अगली पीढ़ी तक पहुंचने में मदद मिल सके। यूथ ट्रैक में 'पर्यावरण और स्थिरता' विषय को कवर करने वाले टॉप 50 आइडियाज़ न केवल गैर- परंपरागत हैं, बल्कि इन्हें भविष्य को ध्यान रखकर लाया गया है। वनों की कटाई, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, समुद्री प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन, अनसस्टेनेबल पैकेजिंग और खराब जल प्रबंधन जैसे मुद्दे युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय के रूप में सामने आए हैं।

दूसरी ओर, 'स्कूल' ट्रैक ने 'समुदाय और समावेशन 'थीम के तहत अपने विचार पेश किए हैं। उनके विचार स्कूली छात्रों में मानसिक बीमारी, LGBTQ समुदाय के लिए समावेशी माहौल की कमी, समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों में डिजिटल साक्षरता की खराब स्थिति और नौकरी के लिए तैयार होने के लिए एकेडेमिक शिक्षा और

तकनीकी कौशल के बीच मौजूदा अंतर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधानों पर केंद्रित हैं।

100 टीमों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 232 प्रतिभागी अब 'सॉल्व फॉर टुमॉरो' प्रतियोगिता के अगले चरण के लिए तैयार होंगे। यहां उन्हें विशेषज्ञ प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के जरिए प्रजेंटेशन और असरदार ढंग से बात करने के कौशल से लैस किया जाएगा। इससे उन्हें जुलाई के मध्य में शुरू होने वाले रीजनल राउंड की तैयारी में मदद मिलेगी।

सैमसंग साउथवेस्ट एशिया के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट एसपी चुन ने कहा 'सैमसंग का मानना है कि हमारे युवाओं में सकारात्मक सामाजिक बदलाव लाने की अपार शक्ति और क्षमता है। इस साल पहली बार, हमने पांच क्षेत्रों - उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और उत्तर-पूर्व के सुदूर इलाकों में भी जाने का फैसला किया है, इससे देश के दूरदराज के क्षेत्रों से भी भागीदारी बढ़ेगी। हमें कुछ बहुत ही अच्छी तरह से व्यक्त किए गए विचार मिले हैं, और युवाओं से इस तरह की प्रस्तुतियां और विचारों की स्पष्टता देखना अविश्वसनीय रूप से प्रेरणादायक है।'

आईआईटी-दिल्ली के एफआईटीटी के एमडी प्रो. प्रीति रंजन पांडा ने कहा, 'सैमसंग सॉल्व फॉर टुमॉरो इस साल पर्यावरण, समुदाय और समावेशन जैसे विषयों को सपोर्ट करने का उद्देश्य लेकर चल रहा है। अलग-अलग ट्रैक - यूथ और स्कूल - ने सभी प्रतिस्पर्धी टीमों को समान अवसर और एक समान मंच दिया है। देश भर के युवा दिमागों से इस तरह के विचारोत्तेजक विचारों को आते देखना एक शानदार अनुभव है। सैमसंग के साथ मिलकर, हमारा प्रयास अगली पीढ़ी में समस्या-समाधान की मानसिकता को प्रोत्साहित करना है जो देश में स्टार्ट-अप के क्षेत्र को बेहतर बनाने में उत्प्रेरक का काम करेगी'।

एयर इंडिया - विस्तारा एयरलाइन के मर्जर को डीजीसीए ने दी हरी झंडी

नई दिल्ली। एजेंसी

टाटा ग्रुप के एयर इंडिया को आखिर कर डीजीसीए की भी हरी झंडी मिल गई। अब टाटा और सिंगापुर एयरलाइन के ज्वाइंट वेंचर एयरलाइन कंपनी विस्तारा का मर्जर एयर इंडिया में हो जाएगा। इस मर्जर को कंपीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया या सीसीआई की अनुमति पहले से ही मिल चुकी है। एयर इंडिया पहले टाटा ग्रुप की ही कंपनी थी। बाद में इसे भारत सरकार ने ले लिया था। कुछ साल पहले भारत सरकार ने इसे बेच दिया था। अब यह फिर से टाटा के पास आ गई है।

डीजीसीए से मिली अनुमति

देश में एविएशन सेक्टर के नियामक डीजीसीए ने सोमवार को विस्तारा को एयर इंडिया में और पूर्ववर्ती एयरएशिया इंडिया को एयर इंडिया एक्सप्रेस में विलय करने की मंजूरी दे दी। अब केवल वर्ष के अंत तक मर्जर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा एयर इंडिया में विदेशी निवेश के लिए मंजूरी की आवश्यकता है। इस समय जहां विस्तारा में एंई की 49इ हिस्सेदारी है, वहीं विलय के बाद एयर इंडिया

में इसकी 25.1% हिस्सेदारी होगी।

आभार व्यक्त किया

एयर इंडिया के सीईओ और एमडी कैंपबेल विल्सन ने इस अवसर पर कहाः 'यह टाटा समूह की एयरलाइंस के विलय में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और हम विलय प्रक्रिया के लिए समय पर मंजूरी के मामले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय से प्राप्त समर्थन के लिए आभारी हैं।' विल्सन ने कहा कि डीजीसीए ने टाटा समूह की सुरक्षा-प्रथम प्राथमिकताओं के अनुरूप अपनी टीमों को सुरक्षा-प्रथम परिवर्तन प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ निर्देशित किया था।

सीसीआई से पहले ही मिल चुकी है मंजूरी

विस्तारा में एयर इंडिया के मर्जर संबंधी प्रस्ताव को कंपीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की मंजूरी पिछले साल सितंबर में ही मिल गई है। बस, इस पर डीजीसीए की हरी झंडी मिलनी बाकी थी। उल्लेखनीय है कि एयर इंडिया और विस्तारा, दोनों फुल सर्विस कैरियर हैं। जबकि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस कम किराये वाली एयरलाइन हैं।

मर्जर के बाद क्या होगा

मर्जर के बाद एयर इंडिया (विस्तारा का इसमें विलय) फुल सर्विस कैरियर बनी रहेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस (इसमें एयर एशिया इंडिया का विलय हुआ) इसकी कम किराये वाली शाखा होगी। कंपनी या विमान का प्रकार बदलते समय पायलटों को क्रॉसओवर प्रशिक्षण से गुजरने से पहले एयरलाइन को डीजीसीए की अनुमति अनिवार्य थी।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जारी किया जाएगा ग्लोबल टेंडर

शुरू होगी चारधाम की यात्रा

नई दिल्ली। एजेंसी

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ाने शुरू कर दी जाएंगी। बता दें कि नोएडा में 2 बार हेलीपोर्ट योजना की ग्लोबल टेंडर होने के बाद भी योजना को पूरा नहीं कराया जा सका है। इसी तर्क पर काम करने के लिए अब नोएडा प्राधिकरण की तरफ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NIAL) सुझाव लेने की बात

कही है, जिससे यहां हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा सके। नोएडा में बनाए जाने वाला हेलीपैड 4 धाम की यात्रा के साथ ही 500 किलोमीटर की रेंज में आने वाले सभी धार्मिक स्थलों तक ले जाया जा सकेगा। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बनाई गई, यह योजना सेक्टर 151 -ए में प्रस्तावित की गई है।

खर्च होंगे करोड़ों रुपए

इस परियोजना में अगर लागत की बात की जाए तो अनुमानित लागत 43.13 करोड रुपए बताई जा रही है, जिसमें इसकी डिजाइनिंग बेल 412 के अनुसार तैयार किया गया है. इसके साथ ही हेलीपोर्ट में 5 बेल 412 के पार्किंग की सुविधा भी दी गई है।

अलग-अलग कंपनियों से मांगे गए सुझाव

हेलीपोर्ट बनाने को लेकर संचालन कंपनियों को यह योजना इकोनामिक के रूप में बोली नहीं लगी है। इसके टेंडर को लेकर कई शर्ते रखी गई है। यही नहीं नियम शर्तों के अनुसार भी तैयार नहीं किया गया है। वहीं, अगर बात प्राधिकरण कार्यालय की करें तो यहां पर हेलीकॉप्टर संचालन करने वाली कंपनियों को बुलाकर उनसे सुझाव लिया गया था। जिसके बाद सुझाव पर ठीक तरह से अधिकारियों ने अमल नहीं किया। यही वजह है कि कंपनियों ने टेंडर में अच्छी रुचि नहीं दिखाई. जहां दो बार ग्लोबल टेंडर जारी होने के बाद भी सिर्फ एक ही कंपनी टेंडर को भरने आई है।

सैमसंग ने एआई-पावर्ड डिजिटल उपकरणों के लिए 'बीस्पोक एआई डेज़' ऑफर्स पेश किये

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत के सबसे बड़े कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सैमसंग ने अपने बीस्पोक एआई-पावर्ड डिजिटल उपकरणों की रेंज पर शानदार ऑफर्स का एलान किया है। इन ऑफर्स के साथ, सैमसंग एआई को आम लोगों में लोकप्रिय बनाना चाहता है और अपने डिजिटल उपकरणों को ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं तक पहुंचाना चाहता है। सैमसंग के बीस्पोक उपकरणों की नई रेंज हमारे रोजमर्रा के काम को व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर स्मार्ट जीवनशैली की सुविधा देती है। 5 जुलाई से अगले 10 दिनों के दौरान ग्राहक एआई-पावर्ड लिविंग के फायदों के बारे में जानने के लिए कंपनी के विशेष ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं। ये बीस्पोक एआई-पावर्ड उपकरण उपयोगकर्ताओं को इनकी सेटिंग्स को पर्सनलाइज करने, सभी उम्र के लिए उपयोगकर्ताओं के जरूरत के मुताबिक नियंत्रण प्रदान करने और अधिकतम कार्यक्षमता के लिए त्वरित निदान प्रदान करते हैं। सैमसंग इंडिया के डिजिटल अप्लायंसेज के सीनियर डायरेक्टर सौरभ बैशाखिया ने कहा बीस्पोक एआई के साथ, सैमसंग ने प्रीमियम ग्लोबल टेक्नोलॉजी को भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंचाया है। ये घरेलू उपकरण सभी उपभोक्ताओं को उनके जरूरत के मुताबिक विकल्प, आसान कंट्रोल, असाधारण सुविधा, ऊर्जा की बचत और अत्याधुनिक तकनीक प्रदान करते हैं।

बैंकों पर साइबर अटैक का खतरा, RBI ने भेजा अलर्ट, सिस्टम की 24 घंटे निगरानी करने का निर्देश

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देशभर के बैंकों को संभावित साइबर हमलों के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी है। केंद्रीय बैंक ने विश्वसनीय खुफिया रिपोर्टों के बाद यह निर्देश दिया है। इसमें बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी खतरे का पता लगाने के लिए चौबीसों घंटे अपने सिस्टम की सक्रिय निगरानी करें। 24 जून को जारी एक एडवाइजरी में आरबीआई ने कहा कि संभावित साइबर हमलों के संबंध में प्राप्त विश्वसनीय खुफिया जानकारी के मद्देनजर रेगुलेटेड एंटिटीज को इन खतरों से बचाव के लिए निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने की सलाह दी जाती है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, RBI का यह संदेश सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से पहले

आया था जिसमें बताया गया था कि कई हाई-प्रोफाइल हमलों के लिए कुख्यात ग्रुप LulzSec भारतीय बैंकों को निशाना बना रहा है। माना जा रहा था कि यह समूह निष्क्रिय हो गया है, लेकिन अब यह फिर से सामने आ गया है। बैंकों को किसी भी तरह की घुसपैठ की पहचान करने के लिए नेटवर्क गतिविधियों और सर्वर लॉग की निरंतर निगरानी करनी होती है। आरबीआई का कहना है कि बैंकों को SWIFT, कार्ड नेटवर्क, RTGS, NEFT और UPI जैसे घरेलू रीयल-टाइम फंड ट्रांसफर ढांचे सहित महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए।

कैसे होता है हमला

RBI ने बैंकों को एक रिमाइंडर जारी किया है, जिसमें उनसे DDoS (डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस) हमलों जैसे खतरों से बचाव के लिए मानक नियंत्रण लागू करने का आग्रह किया गया है। इन हमलों में हैकर्स बैंक के सिस्टम पर समन्वित हमला करते हैं, उन्हें ढेर सारे प्रश्नों से भर देते हैं जो वेबसाइट और ऑनलाइन सेवाओं पर ग्राहक अनुरोधों और लेनदेन की प्रोसेसिंग में बाधा डालते हैं। डीडीओएस सुरक्षा के अलावा, बैंकों को रिमोट लॉगिन और महत्वपूर्ण प्रणालियों तक एक्सेस पर पाबंदी लगाने की आवश्यकता होती है। उन्हें वायरस और मैलवेयर का पता लगाने के लिए सभी सूचना प्रणालियों का गहन स्कैन भी करना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक परीक्षण के बाद नवीनतम पैच स्थापित किए गए हैं। हाल ही में जारी आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र को निशाना बनाकर साइबर घुसपैठ और डिजिटल हमलों में खतरनाक वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। पिछले दो दशकों में, इन घटनाओं के परिणामस्वरूप ₹20 अरब का चौंका देने वाला नुकसान हुआ है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता, जैसे कि भू-राजनीतिक तनाव के समय साइबर हमले बढ़ जाते हैं। इससे विघटनकारी परिणाम सामने आते हैं।

बैंकों की तैयारी

इंडस्ट्री के एक अधिकारी ने कहा कि करीब एक साल पहले रेगुलेटर और CERT-In ने भी इसी तरह का निर्देश जारी किया था। आम तौर पर, जब किसी साइबर हमले का कोई संकेत मिलता है, तो बैंक अपनी तैयारियों का परीक्षण करते हैं। इस बार भी ऐसा ही है। आरबीआई का कहना है कि बैंकों को मजबूत ऑफलाइन बैकअप और रिकवरी रणनीतियां अपनाने तथा उनकी प्रभावशीलता का परीक्षण करने पर फोकस करना चाहिए। अधिकारी ने आगे कहा कि हमलों की अनेक घटनाओं को देखते हुए खुफिया सूचनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।